भारतीय कृषि के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण

श्री प्रदीप्त कुमार साहू
बिजनेस हेड, सफल एवं इंटरनेशनल बिजनेस, मदर डेयरी

कृषि उत्पादन खाद्य सुरक्षा का आधार है और खाद्य प्रसंस्करण आर्थिक और सामाजिक रूप से टिकाऊ तरीके से कृषि में विकास का मार्ग है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) भारतीय अर्थव्यवस्था के दो मुख्य स्तंभों कृषि एवं उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि 2030 तक भारत की वार्षिक घरेलू खपत चौगुनी हो जाएगी, जिससे यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और इसका उत्पादन 2025–26 तक 535 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

महामारी के बाद स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की बदलती आवश्यकता खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी और कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाएगी।

देश में भोजन के तीन कारक हैं–उपलब्धता, पहुंच और अवशोषण। घरेलू उत्पादन के संदर्भ में भोजन की "उपलब्धता" काफी उचित है जबकि "पहुंच" उपभोग के लिए उपलब्ध भोजन के भौतिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। यहां "अवशोषण" का तात्पर्य मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का उपयोग करने की क्षमता से है। यह बदले में खाद्य प्रसंस्करण की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता से भी संबंधित है। हालाँकि इसे सक्षम करने के लिए सार्वजनिक नीति का समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में, दृष्टि और उचित कार्रवाई दोनों की आवश्यकता है।

विश्व स्तर पर, भोजन की उपलब्धता, सुरक्षा और मूल्य प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करने की प्रतिस्पध ा चल रही है। खोज शुरू होती है और खाद्य आवश्यकताओं के लिए हमारे दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए प्रसंस्करण पर समाप्त होती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित निवेश 2019–20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो देश में कुल जीवीए का 1.69 प्रति ात योगदान देता है (खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 2021)। भारत सरकार ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण निध ारित किया है। इन्वेस्ट इंडिया पहल ने अप्रैल 2021–मार्च 2022 की अवधि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 709.72 अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है।

हमारे भोजन का खेत से थाली तक पहुंचने का रास्ता लगातार बदल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य कच्चे कृषि उत्पादों को मानव उपभोग के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना है। कटाई, सफाई, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, संरक्षण और परिवहन जैसी रूपांतरण प्रक्रियाएं पूर्वापेक्षाएँ हैं। कृषि से प्राप्त कच्चे उत्पादों का प्रसंस्करण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से किया जाता है। इस क्षेत्रमें पौधों पर आध ारित मांस, खाने के लिए तैयार भोजन या न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे नए रुझानों को शामिल करने के लिए नवाचार करना जारी है। भारत में कृषि से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख उप–खंड खाद्यान्न, फल और सब्जियां, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी, आदि हैं।

हालाँकि वर्तमान में, भारत में यह क्षेत्र शुरुआती चरण में है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें आशाजनक वृद्धि देखी गई है। भारत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दोनों में लाभ की रक्षा करने, लाभ का विस्तार करने और नए लाभ अर्जित करने की दिशा में काम कर रहा है।

लाभ का बचाव

देश का खाद्यान्न उत्पादन 330.5 एमएमटी (कृषि मंत्रालय, 2022–23) तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि दूध उत्पादन 221.1 एमएमटी (एनडीडीबी, 2021–22) तक पहुंच गया है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रति दिन (एनडीडीबी) बताई गई है जो पहले से ही विश्व औसत 305 ग्राम प्रति दिन (जीएआईएन, यूएसडीए रिपोर्ट 2022) से अधिक है। इसके अलावा, भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (मत्स्य पालन मंत्रालय को 2022–23 में 174 लाख टन की उम्मीद है), चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक (2022–23 में निर्यात मूल्य 63,969 करोड़ के करीब), और सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता है। और मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यातक (स्पाइस बोराड का अधिसूचित उत्पादन 2021–22 में 15.31 लाख टन और 2022–23 में 31761 करोड़ रुपये का निर्यात है) और फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (कृषि मंत्रालय द्वारा 351 एमएमटी उत्पादन रिकॉर्ड करने की संभावना है) 2021–22) विश्व फल और सब्जियों के उत्पादन में 12 प्रति ात के करीब हिस्सेदारी के साथ।

लाभ का विस्तार

इसके अलावा, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य संगठित दूध प्रबंधन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 41 प्रतिशत करना है, जिसमें सहकारी डेयरियों द्वारा दूध प्रबंधन को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और निजी क्षेत्र द्वारा 10 प्रतिशत से 30 प्रति ाततक बढ़ाने का लक्ष्य है (एनडीडीबी)। खाद्य और अनाज क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, अनाज और बाजरा के प्रसंस्करण से लेकर उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे स्नैक्स, पकाने के लिए तैयार या खाने के लिए तैयार उत्पाद, बेकरी आदि के लिए निवेश का अवसर मौजूद है। मत्स्य पालन और समुद्री क्षेत्र में सांकेतिक अवसर में उन्नयन और क्षमता विस्तार शामिल है। कोल्ड चेन के लिए, बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ और उत्पाद भिन्नता के लिए पैकेजिंग में नवाचार, और मछली पकड़ने के बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, थोक बाजारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। मछली/झींगा अचार, मछली/झींगा करी, भारतीय मसालों के साथ मसालेदार मछली आदि जैसे भारतीय स्वाद वाले मूल्यवर्धित उत्पादों को संसाधित करने की क्षमता मौजूद है। वर्तमान में भारत में फलों और सब्जियों के लिए प्रसंस्करण स्तर 3.3 प्रतिशत (खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय) है। भारत में फलों और सब्जियों में 4.58 प्रतिशत–15.88 प्रति ातकी बर्बादी देखी जाती है, इस प्रकार, बर्बादी को कम करने और बाजार में उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रसंस्करण में अवसर निहित है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2019–20 में कहा गया है कि देश में 41481 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ मौजूद हैं और पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान 12.22 प्रतिशत है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी योगदानकर्ता और लाभ प्राप्तकर्ता हैं। इस क्षेत्र का विस्तार अब देश के पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों तक किया जा रहा है। इसके अलावा, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2018–19 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल उत्पादन रुपये से बढ़ गया। 8.13 प्रति ात की सीएजीआर पर 2014–15 में 9.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2018–19 में 12.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की संख्या 17.73 से बढ़कर 20.05 लाख हो गई है।

नए लाभ अर्जित करना

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बुनियादी ढांचे, भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं और खंडित आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि,

https://doi.org/10.52151/aet2023473.1665

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सरकार पांच वर्षों (2020–25) के दौरान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से रुपये के निवेश परिव्यय के साथ देश में दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापनाउन्नयन की दिशा में काम कर रही है। 10,000 करोड़. इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को पूरे देश में लागू किया गया। ओडीओपी का चयन कच्चे माल के उत्पादन, सूक्ष्म–खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की उपस्थिति, बाजार और सामाजिक–आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी, एफपीओ, सहकारी, सूक्ष्म उद्यमों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। कुल मिलाकर, ओडीओपी योजना के तहत अब तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिलों के 137 अद्वितीय उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की योजना के तहत खाद्य उत्पादों के संरक्षण पर 2017–18 से कुल 272 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई. 72 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बड़े लाभ के लिए, सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए देश भर में 41 मेगा फूड पार्क, 382 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 72 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 469 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं और 46 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पहलों से देश भर में बत्तीस लाख से अधिक किसानों को लाभ होने का अनुमान है। वर्ष 2020 में, मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एन.ए.बी.सी.ओ.एन.) ने इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के तहत फार्म–गेट कीमतों में 12.38 प्रति ात की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार भारतीय कृषि को समर्थन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादों में उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है।

संक्षेप में कहें तो, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास हासिल करने की जबरदस्त क्षमता है, और अगले दशक के लिए इस क्षेत्र का दृष्टिकोण अपनी क्षमता बढ़ाने और भोजन की बर्बादी को कम करने का होना चाहिए। उद्योग, कृषि क्षेत्र, प्रमुख तकनीकी संस्थानों और सरकार को आधुनिक तकनीकों को अपनाकर, नए उत्पाद विकसित करके, और बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करके इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।